केन्द्रीय श्रम मन्त्री ने ई एस आई मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मौका रिपोर्ट तलब की

फ़रीदाबाद (म.मो.) क्षेत्र के 5 लाख मज़दूर परिवारों की ई एस आई निगम द्वारा अनदेखी के बाबत 'मज़दूर मोर्चा' में लगातार खबरें प्रकाशित होने के बाद केन्द्रीय श्रम मन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने गत माह, पहले तो अपने मंत्रालय एवं निगम के उच्चाधिकारियों की मीटिंग बुला कर उन्हें कड़ी फ़टकार लगाई थी। जिससे एन एच 3 में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ठप्प पड़े काम में कुछ प्रगति होने लगी।

इस प्रगति एवं ज़मीनी हकीकत को जानने व समझने के लिये श्रम मंत्री ने दो जनों की एक विशेष टीम को नियुक्त किया। इस टीम में भारतीय मज़दूर संघ के केन्द्रीय नेता कुलकर्णी, जो ई एस आई निगम के सदस्य भी है, तथा मुंबई स्थित ई एस आई मेडिकल कॉलेज की डीन डॉक्टर (श्रीमती) माथुर हैं इन्हें 14 नवम्बर तक अपनी रिपोर्ट मन्त्री को देनी थी लिहाजा टीम ने रविवार दिनांक 9 नवम्बर को अधबने इस मेडिकल कॉलेज अस्पताल का पूरा निरीक्षण किया।

टीम ने अस्पताल में मौजूद वरिष्ठ डॉक्टरों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि तमाम तरह की चिकित्सायें करने में समर्थ हैं लेकिन जब काम करने के लिये कोई औजार एवं उपकरण ही नहीं होंगे तो वे क्या करेंगे। उन्होंने यह भी कहा बताते हैं कि यदि शीघ्र उपकरण आदि नहीं मिलेंगे तो वे यहां बहुत दिन टिकने वाले भी नहीं हैं। दूसरी ओर अस्पताल में चिकित्सा न हो पाने की वजह से आये दिन प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को रैफ़र करना पड़ता है जिस पर करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है।

विदित है कि अस्पताल के लिये आवश्यक सारे-साजो सामान एवं उपकरण आदि खरीदने, स्टाफ़ की भर्ती आदि करने का काम एम एस (चिकित्सा अधीक्षक) को करना होता है जो वे गत 15 माह से नहीं कर पा रहे थे। पूछे जाने पर उन्होंने टीम को बताया कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिये जिस वित्त विभाग की आवश्यकता होती है वह यहां पर नहीं था। हां अभी कुछ दिनों से कुछ स्टाफ़ आया है तो प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर ली जायेगी।

भविष्य निधि सम्बन्धित रिपोर्ट के एक भाग का खंडन

फ़रीदाबाद (म.मो.) गतांक में करनाल से एक खबर 'भविष्य निधि: घोटालेबाज़ों को अधिकारियों का संरक्षण' शीर्षक से प्रकाशित की गयी थी। इसमें अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त जगमोहन का भी उल्लेख किया गया था। इस बाबत जगमोहन ने फ़ोन करके सम्पादक को बताया कि वे दिनांक 12 जुलाई 2014 को चंडीगढ़ तथा कहीं आगे जाते हुए करनाल में रूके जरूर थे लेकिन यह गलत है कि उस वक्त उनके साथ कोई महिला मित्र थी। उनके साथ जो महिला थी वह उनकी धर्मपत्नी थी।

बेशक 12 जुलाई को शनिवार होने की वजह से सरकारी अवकाश था और वे अपनी निजी यात्रा पर चंडीगढ एवं शिमला आदि की ओर जा रहे थे, लेकिन काम का बोझ इतना होता है कि वे लोग जहां तक संभव हो सके आते-जाते रास्ते में पड़ने वाला कोई काम निपटता हो तो वे निपटाने का प्रयास करते हैं। इसलिये सरकारी काम को निपटाने के लिये उन्होंने करनाल कार्यालय के कर्मचारियों को मीटिंग के लिये बुला लिया था। इस काम के लिये यदि वे करनाल का स्पेशल दौरा रखते तो कम से कम एक कार्यदिवस के अलावा वाहन का भी खर्चा होता।

खबर में बताये गये घोटाले के बारे में उन्होंने कुछ विशेष न कह कर केवल इतना कहा कि वे इसकी जांच कर रहे हैं और जिस शिकायती पत्र का हवाला खबर में दिया गया है वह बेनामी है उसमें दिया गया पता ग़लत है। श्री जगमोहन की धर्मपत्नी को महिला मित्र बताने के लिये 'मज़दूर मोर्चा' खेद व्यक्त करता है।

रंगीला प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हालिया अमेरिकी यात्रा के दौरान खबर आई कि वे एक दिन में छ: बार कपड़े बदले थे। अखबारों के चिकने पन्ने ने बताया कि मोदी वहां 'फैशन स्टेटमेंट' बन गये थे और उन्होंने ओबामा दंपत्ति को बहुत पीछे छोड़ दिया।

महत्त्वपूर्ण और गौर करने लायक बात यह है कि मोदी की इस विशेषता के लिए पूंजीवादी हलकों में आलोचना का कोई स्वर नहीं उभरा, भर्त्सना की तो बात ही क्या? किसी ने यह नहीं पूछा कि जिस देश की एक तिहाई आबादी, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भी, भुखमरी में जी रहे हो (वास्तव में दो-तिहाई से ज्यादा) उसमें यह आचरण क्या अश्लील नहीं माना जाना चाहिए। अमेरिका से लौटकर अपने 'सफ़ाई अभियान' में महात्मागांधी का नाम जपनेवाले इस फैशनपरस्त से किसी ने नहीं पूछा कि उसके इस अश्लील आचरण में गांधी की सादगी कहां है।

मजे की बात यह है कि अभी कुछ महीने पहले चुनावों के दौरान इस व्यक्ति के बारे में प्रचारित किया जा रहा था कि संघ का प्रचारक होने के दौरान मोदी के पास दो जोड़ी कपड़े होते थे। मोदी की उस समय की सादगी और आज की फैशनपरस्ती का एक साथ गुणगान किया जा रहा है।

मोदी का यह आचरण और उसका यह प्रचार भारत के पाखंडी मध्यम वर्ग के चरित्र के अनुरूप है। यह वर्ग सादगी की बात करते हुए ऐश करने के सपने देखता है। सादगी इसके लिए वह आदर्श है जो ऐश की पहली संभावना पैदा होते ही चुपचाप रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है।

नरेन्द्र मोदी की अमेरिका यात्रा को बड़ी मात्रा में उस मध्यम वर्ग ने कंधा दिया जो एक एशो-आराम की जिन्दगी के लिए भारत नाम के गरीब मुल्क को छोड़कर अमेरिका पलायन कर चुका है। उसे पलायन करने लायक इस गरीब मुल्क ने ही बनाया था क्योंकि उसकी शिक्षा-दीक्षा का खर्च इस गरीब मुल्क ने ही उठाया था। लेकिन पढ़-लिखकर काबिल बनने के बाद उसे लगा कि यह मुल्क उसके लायक नहीं है और पहला मौका मिलते ही वह अमेरिका पलायन कर गया।

मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान इसने (इसके एक हिस्से ने) वहां उनका खूब स्वागत किया और 'सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां' के गीत गाये। किसी ने इस पर ठीक ही टिप्पणी की कि यदि हिन्दोस्तां इतना ही अच्छा है तो वापस आ जाओ ना! लेकिन इसे तो वापस नहीं आना है। उसे अमेरिका में रहते हुए ही उस हिन्दोस्तां के गीत गाना है जहां से वह पलायन कर गया था।

ऐशो-आराम के लिए अपना मुल्क छोड़कर पलायन कर जाने वाले इस वर्ग के लिए मोदी का दिन में छ: बार कपड़े बदलना अश्लील नहीं बल्कि अनुकरणीय है। यह उसी ऐश की अभिव्यक्ति है जिसके लिए यह वर्ग भारत से अमेरिका गया था। भारत में रह जाने वाले उसके बंधु भी इसी लालसा से प्रस्त हैं इसलिए वे भी मोदी को ईर्ष्या भरी प्रशंसा की नजर से देखते हैं। ऐसे में मोदी को अपना अश्लील आचरण अश्लील क्यों लगने लगा? वे इसे घटिया मानने के बदले अपना 'स्टाइल' क्यों नहीं मानेंगे?

मोदी के 'स्टाइल' का राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर दूरगामी असर होगा। संघ का हर अदना प्रचारक भी इस समय मोदी में अपना भविष्य देख रहा होगा जैसे नेपोलियन के जमाने में हर मध्यम वर्गीय युवक नेपोलियन में अपना भविष्य देखता था। संघ के प्रचारक मोदी के 'स्टाइल' को अपनाने के लिए स्वत: ही प्रेरित होंगे। ऐसे में भागवत जैसे बूढे प्रचारक भले ही सादगी की बात करते रहें पर वे नौजवान प्रचारकों को मोदी का फैशन अपनाने से नहीं रोक सकते। भाजपा तो पहले ही ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट हो चुकी है अब संघ भी अछूता नहीं रहेगा। हिन्दू साम्प्रदायिक संघ के लिए यह कोढ में खाज साबित होगा।

नागरिक

ग्रामीण विद्युतिकरण के नाम पर बड़ा घोटाला

देखें मोदी और मनोहर लाल क्या करते हैं

फ़रीदाबाद (म.मो.) बी पी एल यानी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को बिजली की सुविधा पहुंचाने के नाम पर हरियाणा की हुड्डा सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना की शुरूआत की थी अपने शासन काल के अन्तिम दिनों में। ग़रीबों को बिजली सुविधा पहुंचाने के नाम पर सरकार ने 155 करोड़ रुपये की यह योजना बनाई। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में रहने वाले बी पी एल परिवारों के घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए खंबे गाडकर तारें खींचना, छोटे ट्रांसफ़ार्मर लगाना और फ़िर बी पी एल घरों तक केबल लगाकर बिजली पहुंचाना होता है। इतना ही नहीं घरों तक बिजली पहुंचाने के बाद एक मीटर, एकबी पी एल किट, सी एफ एल बल्ब व एक एम सी बी लगाना होता है।

सरकारी योजना के अनुसार इन सारे कामों के लिए उपभोक्ता से एक भी पैसा नहीं वसूला जायेगा। परन्तु शायद ही कोई घर ऐसा होता होगा जिससे इस काम की अवैध वसूली न होती हो। दरअसल सरकार ने यह सारा काम अपने महकमे से कराने की बजाय दो कम्पनियों को इसका ठेका दे दिया। एक का नाम है एम एन सी (मानसिंह नीरज चौधरी) व दूसरी है इलेक्ट्रोमेक इंजीनियर्स। इन दोनों कम्पनियों ने भी अपने-अपने हिस्से की मलाई खा कर करने वाला काम कई छोटे-छोटे ठेकेदारों को सौंप दिया है।

इन ठेकेदारों ने ज़मीनी स्तर पर काम करने के लिए तरह-तरह के मज़दूरों की भर्ती की है। खंबे गाड़ने के लिए गड्ढे खोदने वाले मज़दूर, बिजली का कनेक्शन करने वाले इलेक्ट्रीशियन तथा इन सब कामों की निगरानी करने वाले सुपरवाइज़र। गड्ढे खोदने वाले अनपढ मज़दूर मध्य प्रदेश व राजस्थान के दूर दराज के इलाकों से बहला फुसला कर लाये जाते हैं जबकि पढे लिखे, जिनमें बेरोजगारी के मारे इन्जीनीयर्स व स्थानीय युवक होते हैं। इन दोनों प्रकार के मज़दूरों

को बताये गये वेतन एवं सुविधाओं का थोड़ा-थोड़ा हिस्सा लटका-लटका कर दिया जाता है और जब अन्त में वह भी बन्द कर दिया जाता है तो वे भाग खड़े होते हैं। इससे ठेकेदारों को वह रकम सीधे-सीधे बच जाती है जो उन्हें वेतन के रूप में देनी थी।

कुछ पढे-लिखे मज़दूर जिनका मीटर लगाते समय उपभोक्ता से सीधा सम्पर्क होता है। इस काम के बदले 100 से 200 रुपया तक झटक लेते हैं। ठेकेदारों को इस बाबत पता होते हुए भी वे चुप रहते हैं क्योंकि वेतन तो वह देता नहीं ऐसे में यही अवैध वसूली ही तो है जिसके सहारे ये लोग चिपके रहते हैं। अच्छी खासी वसूली उन खाते पीते उपभोक्ताओं से भी हो जाती है जो बी पी एल ना होते हुए भी इस योजना के तहत लाभ उठाते हैं। ठेकेदार को इससे कुछ लेना-देना नहीं होता कि लाभ उठाने वाला बी पी एल है या नहीं, उसे तो बस एक नाम-मात्र का प्रमाणपत्र गांव के सरपंच से लेना होता है। ठेकेदार को पेमेंट भी घरों में दिये गये कनेक्शनों की संख्या के आधार पर होती है।

ठेकेदार अपनी कमाई बढाने के लिये जहां खंबे से खंबे की दूरी में हेराफ़ेरी करके खर्च बचाते हैं वहीं इनके बीच लगने वाली तारों की लम्बाई में भी हेराफ़ेरी करते हैं। इसके लिए तारों को उचित रास्तों से निकालने की अपेक्षा लोग़ों के घरों की छतों पर से भी खींच देते हैं जो कि खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा एम सी बी व सी एफ एल बल्ब को तो ठेकेदार सीधे-सीधे डकार जाता है। एम सी बी के बारे में अधिकतर लोग तो जानते ही नहीं यदि कोई पूछ भी ले तो उसे यूं ही गोल-मोल जवाब देकर टरका दिया जाता है। मीटर जो कि लगने से पहले लैबोरेट्री से पास होकर आना जरूरी होता है,परन्तु ठेकेदार इसकी भी कोई जरूरत नहीं समझते और सीधे ही बिना पास कराये लगा देते हैं।

श्रमिकों का वेतन मारने व सामान की चोरी करने वाले ये ठेकेदार जो सामान लगाते भी हैं वह भी निहायत घटिया किस्म का होता है। इतना ही नहीं जिस तौर-तरीके से यह सामान लगाया जाता है वह भी ऐसा होता है कि बस उतने ही दिन टिक पाता है जब तक सरकार से ठेकेदार को पेमेंट ना हो जाय। कुल मिलाकर सारा काम फ़र्जी एवं दिखावे मात्र का होता है। यह सारा काम आम जनता के लाभ के लिये न होकर ठेकेदारों, अफ़सरों व नेताओं की जेब-भराई के लिए ही होकर रह जाता है। कहने की जरूरत नहीं कि सरकार की ओर से इस तरह के ठेके केवल उन्हीं को दिये जाते हैं जिनकी विभागीय अधिकारियों तथा राजनेताओं में अच्छी पैंठ होती है, पैंठ यानी लेने-देने का सिलसिला तय होता है। सर्वविदित है कि पेमेंट हो चुकने के बाद ठेकेदार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता चाहे सारे खंबे गिर जायें, तारें लटक जायं या टूट जायें, ट्रांसफ़ार्मरों में आग लग जाये, उनसे होनेवाली दुर्घटना में बेशक कोई मर जाये पर ठेकेदार को कोई नहीं पूछ सकता। पूछेगा तो कोई तब ना जब ठेकेदार ढूंढे से भी कहीं मिलेगा। यही काम यदि विभाग स्वयं ईमानदारी से करे तो गुणवत्ता के लिये उसके अधिकारी उत्तरदायी होंगे सदैव के लिये। इसके अलावा ठेकेदारों द्वारा जो मज़दूरों की मेहनतकश की लूट होती है उसे भी रोका जा सकता है।

प्रशासन की नालायकी के चलते हथीन फ़िर भड़का

पलवल (म.मो.) एक पखवाड़े के भीतर हथीन में दूसरी बार फ़िर कर्फ्यू लगा। दिनांक 10 नवम्बर को, लिखित समझौते का उल्लंघन करते हुए, एक सम्प्रदाय के लोग़ों ने विवादित स्थल पर जाकर धर्म का पाखंड करना चाहा। प्रशासन ने जब उनको नहीं रोका टोका तो दूसरे सम्प्रदाय के लोग़ों ने विरोध किया। विरोध करते ही दंगा फ़साद शुरू हो गया। पहले आस-पास के बोंगे गिटोड़ों में आग लगाई गयी फ़िर, प्रशासनिक निष्क्रियता को देखते हुए भीड़ घरों तथा दुकानों तक भी तोड़-फ़ोड़ करने लगी। जब तक प्रशासन सक्रिय हुआ तब तक कई घर, दुकानें तथा वाहन आदि तबाह हो चुके थे। एक पेट्रोल पम्प से तो करीब लाख रुपया नकद लूट लिया गया जब हालात बिल्कुल बेकाबू हो गये तो कर्फ्यू का सहारा लेना पड़ा। गतांक में सुधि पाठकों ने पढा होगा कि यह विवादित स्थल पुलिस के उस थाना परिसर में है जिसे नया थाना बनने के बाद खाली कर दिया गया है। लेकिन थाना स्थानांतरित होने के बावजूद इस जगह पर कब्ज़ा पुलिस का ही है। पुलिस ने वहां पर बाकायदा सी आई ए (पुलिस) की चौकी बना दी है। नया थाना भी घटना स्थल से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इस छोटे से कस्बे में डी एस पी व एस डी एम की भी स्थाई तैनाती है। ज़िला मुख्यालय, जहां एस पी व डी सी तैनात हैं, भी मात्र 20 मील की दूरी पर स्थित है। इस सबके बावजूद यहां पर इतनी भयंकर प्रशासनिक अव्यवस्था अथवा लापरवाही सिद्ध करती है कि सरकार चलाने वाले अर्थात ज़िला एवं तहसील स्तर पर तैनातियां करने वाले ही नालायक बैठे हैं।

जानकार बताते हैं कि पुराने थाने के परिसर में जो सी आई ए चौकी है उसके ही कुछ मुलाजिमों की मिलीभगत एवं शह पर ही उत्पाती लोग़ों ने विवादित स्थल पर आकर धार्मिक पाखंड करने का प्रयास किया था। यहां समझने वाली बात केवल इतनी है कि हथीन एवं पलवल में तैनात अफ़सरान इतने नालायक हैं कि उन्हें अपने मातहत मुलाज़िमों के चरित्र एवं स्तर का भी ज्ञान नहीं है। उनका अपने मातहतों पर कोई नियन्त्रण नहीं है और न ही उन्हें नियन्त्रित करने का कोई प्रयास किया गया।

इतना काम कवाड़ा होने के बाद एस पी पलवल का तबादला किया गया है। जिन अफ़सरों ने अब उसका तबादला किया है, उन्हें उसकी योग्यता समझने में इतना समय लगा? सब कुछ जला कर होश में आये तो क्या आये। अब तो उन अफ़सरों का तबादला होना चाहिये था जो एस पी व अन्य दोषी अफ़सरों को वहां लगाये बैठे रहे।

मज़दूरों ने सबक सिखाया

फ़रीदाबाद (म.मो.) औद्योगिक क्षेत्र में एक मथुरा रोड, सराय ख्वाजा, अमर नगर के पास 'भारत गियर' के नाम से कम्पनी है जिसमें गाड़ियों के गियर बनते हैं। इस कम्पनी में लगभग 1000 हज़ार मज़दूर काम करते हैं। काम तीन शिफ्टों में होता है। 200 के करीब परमानेन्ट मज़दूर जिनकी तनख्वाह 8000 रुपये से लेकर 10000 तक है। 250 के करीब डिप्लोमा किये हुए मज़दूर हैं। नान टेकनिक 300 मज़दूर व ठेकेदारी के मज़दूर 200 के करीब कार्यरत हैं। इस तरह कम्पनी मैनेजमेण्ट ने मज़दूरों को अलग-अलग कैटेगरी में बांट रखा है जिससे एकता में बाधा पहुंचती है। जिस तरह मैनेजमेण्ट यह चाहता है कि मज़दूर आपस में बंटे रहे। स्थाई के नाम पर, डिप्लोमा के नाम पर, ठेकेदारी मज़दूर के नाम पर ताकि इनका कोई संगठन या एकता ना बन जाये। हां, यहां अच्छी बात है कि सीटू की यूनियन है जिसमें सिर्फ परमानेन्ट सदस्य हैं लेकिन स्थायी मज़दूरों का ठेकेदारी मज़दूर व कैजुअल मज़दूरों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैनेजमेण्ट चाहती भी है।

ठेकेदारी के मज़दूर व कैजूअल मज़दूर को कोई भी अवकाश नहीं मिलता। इनकी दिहाड़ी के हिसाब से तनख्वाह 6000 से लेकर 7000 रुपये तक महीना मिल जाती है। कोई भी त्यौहार या राष्ट्रीय पर्व की छुट्टी नहीं दी जाती। अगर कम्पनी में छुट्टी रहती है तो पैसे काट लिये जाते हैं। सिंगल ओवर टाइम मिलता है। वहीं पर परमानेन्ट मज़दूर को छुट्टी मिलती है डबल ओवर टाइम मिलता है। यूनियन को संघर्ष करने के बजाय मैनेजमेण्ट के एक लालच में फंस गयी है। वह यह उत्पादन अच्छे निकलने पर इनाम दिया जाता है तो सिर्फ़ स्थायी को लेकिन काम का ज्यादा भार कैजुअल व ठेकेदारी के मज़दूर पर पड़ता है।

इस तरह अलग-अलग कैटेगरी में बांट कर, छोटा सा लालच देकर आपस में बांट रखा है, जो मैनेजमेण्ट हर समय, हर वक्त चाहती है। एक घटना हमें सोचने को मज़बूर करती है कि एक लाइन पर रात की शिप्ट में सुपरवाइजर आकर यह कहता है कि सात कैजुअल मज़दूर जो सात मशीन को चलाते हैं अब तीन मज़दूर चलायेंगे। मज़दूर अड़ जाते हैं। कहते हैं कि प्रोडक्शन नहीं निकल पायेगा। सुपरवाइजर जिद पर अड़ जाता है। यूनियन के मज़दूर सदस्य अपनी बहादुरी के संघर्ष के बदौलत सारे लाइन की मशीनें बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। सारे मज़दूर साथ देते हैं। इस तरह की एक छोटी घटना ने 2 घंटे के करीब काम बंद कराकर मैनेजमेण्ट को सबक सिखाया गया। प्रधान से लेकर यूनियन के बाकी सदस्यों ने सुपरवाइजर को लताडा व बेइज्जती की। सुपरवाइजर ने दमखम लगाया। फोन पर फोन करके मैनेजर तक से बातें कीं लेकिन रात में यूनियन प्रधान ने आकर मामले को हाथों में लेकर सुपरवाइजर की डांट-फटकार लगाई और कहा कि जितने घंटे मशीनें बंद रही सब इस सुपरवाइजर के नाम डाल दो।

इस बढते प्रोडक्शन व आधुनिक मशीनों की रफ़्तार में मज़दूर खुद मशीन बन जाता है। काम का बोझ लगातार बढ रहा है। पूंजीपति आज मज़दूर को कैजुअल व ठेकेदारी में रखना पसंद करता है। क्योंकि मज़दूरों का संघर्ष कमजोर पड़ा है। इस कम्पनी में जब यूनियन बनी तो बहुत से मज़दूर साथियों ने संघर्ष किया था। आज मज़दूर उस संघर्ष को भूल रहे हैं कभी तो ठेके के नाम पर कभी कैजुअल के नाम पर भर्ती होती है। नये सिरे से किसी मज़दूर को स्थायी नहीं किया जाता है। छोटी-छोटी लालच देकर स्थायी मज़दूरों को बाकी मज़दूरों से काटने का काम करती है मैनेजमेण्ट हर सम्भव यह प्रयास करती रहती है। आज जरूरत है कि स्थायी, ठेका मज़दूर व कैजुअल मज़दूर के साथ में लेकर एकता बनाकर संघर्ष किया जाये या सबसे बड़ी बात यूनियन को बचाना है तो साथ मिलकर लड़ा जाये।